संख्या- 324/2025/951/41-1-2025-CN-1800973-2023

प्रेषक,

संजीव कुमार श्रीवास्तव,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन उ०प्र०, तखनऊ।

पर्यटन अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 28 मार्च, 2025

विषय जनपद बलिया के विकास खण्ड नगरा ग्राम सभा निकासी स्थित प्राचीन तालाब का सौन्दर्याकरण व सीढ़ियों का निर्माण कार्य हेतु पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 10880/6-1-1(05)/2024-25, दिनांक 21 मार्च, 2025 का कृपया सन्दर्भ ग्राण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद बलिया के विकास खण्ड नगरा ग्राम सभा निकासी स्थित प्राचीन तालाब का सौन्दर्गीकरण व सीर्टियों का निर्माण कार्य हेतु परियोजना की नामित कार्यदायी संस्था उ०प्र० राज्य पर्यटन विकास निगम लि० द्वारा गठित आगणन रू0 108.11 लाख को प्रेषित करते हुए परियोजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि प्रश्नगत परियोजना हेतु उ०प्र० राज्य पर्यटन विकास निगम लि० (UPSTDC) को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए शासनादेश संख्या-401/1052-41-1-2024-सी०एन० 1800973-2024, दिनांक 16 मार्च, 2024 द्वारा रू0 108.11 लाख (जी०एस०टी० सहित) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा प्रथम किश्त के रूप में रू0 0.75 लाख तथा शासनादेश संख्या-617/2024/1428-41-1-2024-सी०एन०-1800973-2024, दिनांक 29 जून, 2024 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में रू0 70.00 ताख, इस प्रकार अब कुल रू0 70.75 लाख की धनराशि निर्गत की गयी है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद बलिया के विकास खण्ड नगरा ग्राम सभा निकासी स्थित प्राचीन तालाब का सौन्दर्यकरण व सीढियों का निर्माण कार्य हेतु अप्रेजल समिति द्वारा आंकलित धनराशि रू0 108.11 लाख की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) भू-अभिलेख, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र, त्रिपक्षीय अनुबन्ध, रख रखाव हेतु बैंक खाता एवं 26 विन्दुओं की सूचना उप निदेशक, पर्यटन, गोरखपुर द्वारा उपलबध कराये जाने के पश्चात ही आगणन स्वीकृति हेतु शासन प्रेषित किया जायेगा।

(2) सपरोक्त प्रपत्रों को उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(3) प्रश्नगत परियोजना हेतु पूर्व में निर्गत पर्यटन अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-401/1052-41-1-2024-सी०एन०-1800973-2024, दिनांक 16 मार्च, 2024 एवं शासनादेश संख्या-617/2024/1428-41-1-2024-सी०एन०-1800973-2024, दिनांक 29 जून, 2024 में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(4) प्रश्नगत कार्य की निविदा में ई-टेन्डरिंग की प्रक्रिया लागू की जायेगी। ई-टेन्डरिंग प्रक्रिया में आई०टी० एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-3/2017/1067/78-2-2017-42-आईटी/2017, दिनांक 12.05.2017 एवं समय समय पर के आदेशों/निदेशों में निहित शर्तों एवं प्राविधानों का अनुपालन पूणतया सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) परियोजना का निर्माण कार्य प्राराम करने से पूर्व मानचित्रों की आवश्यकतानुसार स्थानीय विकास प्राधिकरण/ सक्षम लोकत अधोरिटी से लीकृत करा लिया जावेगा तथा नियमानुसार विभिन्न संस्थाओं से समस्त आवश्यक वैधानिक अपतिमा एवं पर्यावरणीय एवं सक्षम स्तर से प्राप्त कर लिया वायेगा एवं अन्य सम्बन्धित संस्थाओ विभागों प्राधिकरणों आदि से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त किया जाना सुनिक्षित किया जायेगा।

(6) प्रश्नगत कार्य पर धनराशि का नियमानुसार व्यय टेण्डर लागत के आधार पर वास्तविक रूप से किया जायेगा। यदि कोई धनराशि अवशेष बनती है तो उसे राजकोष में जमा किया जायेगा।

(7) प्रश्नगत निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन तैयार कर सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्रापा करने के साथ-साथ विज्ञीष हस्त पुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्थानुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर के तकनीकी स्वीकृति के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा तथा उस पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात ही प्रायोजना के निर्माण हेतु दूसरी किश्त निर्गत की जायेगी।

(8) प्रश्नगत परियोजना हेतु व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-2/2024/बी 1 294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04.03.2024 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) प्रायोजना के निर्माण कार्य में वस्तु एवं सेवाकर (जी०एस०टी०) की धनराशि कार्यदायी संस्था को वास्तविक भुगतानके अनुसार नियमानुसार अनुमन्य होगी तथा इस सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था द्वारा जी०एस०टी० भुगतान के सम्बन्ध में प्रामाणिक प्रपत्र जी०एस०टी० इन्वायस एवं धनराशि के भुगतान का पूर्ण प्रमाणित विवरण सक्षम स्तर से महानिदेशक पर्यटन के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त लेबर सेस के रूप में प्रदान की गयी धनराशि श्रम विभाग को भुगतान किये जाने का प्रमाण पत्र कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ उपलब्ध कराया जायेगा।

(10) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय समय पर कार्यदायी संस्था द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों का पर्यवेक्षण (मानीटरिंग) महानिदेशक, पर्यटन द्वारा सुनिश्चित कराया जाय। स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) प्रश्नगत परियोजना में होने वाले निर्माण कार्य के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि निर्माण कार्य आगणन के अनुरूप उसके तकनीकी अनुमोदन के अनुसार किया गया है तथा परियोजना को कार्यदायी संस्था से हस्तगत कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करा लिया जायेगा एवं निर्मित परिसम्पत्ति का समुचित रख-रखाव सुनिश्चित किया जायेगा एवं इसकी अद्यतन प्रगति रिपोर्ट ई-परियोजनाओं की समीक्षा के पोर्टल पर अंकित कराते हुए शासन को अवगत कराया जायेगा।

(12) परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रपत्र पर सक्षम स्तर से शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। सोशल आडिट से सम्बन्धित व्यवस्था/नियमों का भी पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(13) पह सुनिक्कित किया जाता कि उपरोक्तकिकृत धनराशि प्राप्त न की गयी हो। यह भी सुनिक्षित किया कि इसकी थीतों से भविष्य में अन्य योजनाओं में द्विरा पुरावृति होऔर इसके रस रसान हेतु राज्य सरकार के ऊपर वाम भार न पड़े। कार्यदायी संस्था से कार्य की समाप्ति के पश्चात सम्प्रेक्षित लेखे अनिवार्य रूप से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(14) प्रायोजना में संशोचित पुनरीक्षित प्रशासकीय सीकृति कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय द्वारा उपलब्बा करायी गयी सूचना/ विवरण के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि परियोजना के मानक के सम्बन्ध में कोई सूचना गतत पायी जाती है तो इसका पूर्ण उत्तदावित्व कार्यदापी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय एवं क्षेत्रीय अधिकारियों का होगा। प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष वास्तविक रूप से व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र/कार्य की गुणवत्ता एवं फोटोग्राफ्रा आदि सक्षम सार से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(15) कार्य की विशिष्टियों, मानक एवं गुणवत्ता आदि की पूर्ण जिम्मेदारी महानिदेशक, पर्यटन एवं कार्यदायी संस्था की होगी तथा उनके द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाय। इसके लिए परियोजना में टाइम ओवर-रन/कास्ट ओवर रन को नियन्त्रित करने के सम्बन्ध में विज्ञ (आय-व्ययक) अनुभाग 1 के शासनादेश संख्या-07/2017/बी-1 823/दस-2017-एम-04/2017 दिनांक 21 जून, 2017 में दिये गये निर्देशों तथा बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 (VII) में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा प्रायोजना का पर्टचार्ट कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर शासन को शीघ्र उपलब्ध कराया जाय।

(16) प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व भूमि की वैधानिक उपलब्धता सुनिश्चित करा ली जायेगी तथा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त कर लिया जायेगा। सोशल आडिट से सम्बन्धित व्यवस्था/नियमों का भी पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(17) सोलर लाइट/सौर ऊर्जा से सम्बन्धित लाइटों/उपकरणों का क्रय उ० प्र० नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (UPNEDA) से नियमानुसार क्रम किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(18) प्रायोजनान्तर्गत निहित विशिष्टि प्रकार की लाइट फिटिंग्स एवं फिक्चर्स, जो बाजार दरों/कोटेशन पर आधारित हैं, की दरों को न्यूनतम एवं वास्तविक दरों पर कराये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व पर्यटन निदेशालय/कार्यदायी संस्था का होगा।

(19) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित बाट आउट आइटम के कार्यों हेतु पर्यटन निदेशालय/कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जायेगा।

(20) प्रायोजनान्तर्गत सेंटेज चार्जेज (प्रतिशत प्रभार), निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से संबंधित वित्तीय प्रबन्धन के संबंध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 एवं शासनादेश संख्या-

---

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 19 मई, 2023 में निहित दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी ।

(21) परियोजनान्तर्गत बाट आउट आइटम्स पर पर्यटन अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2764/41-1-2024-सी०एन०-1864107/2024 दिनांक 07 नवम्बर, 2024 द्वारा गठित क्रय समिति का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

(22) परियोजना के कार्य पूर्ण होने के उपरान्त परिया की क्लोजर रिपोर्ट एक पक्ष के भीतर उपलब्ध करागी वापेगी। परियोजना की रिपोर्ट उपकराये जाने की स्थिति में उक्त कुरा को अनियमितता मानते हुए सम्बन्धित परियोजना प्रबन्धक अपर परियोजना प्रबन्धक एवं ठेकेदार के विरूद्ध नियमानुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ० आई० आर०) दर्ज कराने की कार्यवाही पर्यटन निदेशालय/सम्बन्चित क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी उपनिदेशक, पर्यटन द्वारा की जायेगी।

4- यह आदेश वित-आय व्ययक अनुभाग के शासनादेश संखा 2/2024/बी 1 294/68-2024 231/2024, दिनांक 04.03.2024 में प्रशासकीय विभाग को उकावत प्राविधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव।

<u>संख्या व दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
3. निजी सचिव, मा० मंत्री, पर्यटन विभाग, उ०प्र० शासन।
4. जिलाधिकारी, बलिया।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य पर्यटन विकास निगम लि०, लखनऊ ।
7. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
8. क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी (राज्य योजना), पर्यटन निदेशालय, लखनऊ ।
9. उप निदेशक, पर्यटन, आजमगढ/गोरखपुर मण्डल ।
10. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
11. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in